‘गति शक्ति’ से घट रही लागत

मंत्री पीयूष गोयल बोले — लॉजिस्टिक सुधार से उद्योगों को बड़ा लाभ

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन’ देश के बुनियादी ढांचे को रूपांतरित कर रही है और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार ला रही है. इस मिशन के चलते अब इसके ठोस परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देने लगे हैं.

मिशन बना योजनाबद्ध विकास का प्रमुख साधन

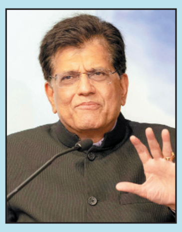

गोयल ने बताया कि पिछले चार वर्षों में पीएम गति शक्ति मिशन ने मंत्रालयों, राज्यों और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का एक प्रभावी उपकरण बनकर उभरना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा, अब हर कोई इस पहल से लाभ उठा सकता है. इसका प्रभाव दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है.

भारत मंडपम में पीएम गति शक्ति मिशन की चौथी वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि वर्षों से भारत की प्रतिस्पर्धा के लिए चुनौती बनी लॉजिस्टिक लागत अब घटने लगी है. उन्होंने बताया कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ है कि विशेष रूप से लास्ट माइल कनेक्टिविटी में सुधार के कारण लॉजिस्टिक लागत में उल्लेखनीय कमी आई है.गोयल ने बताया कि पहले उद्योगों को सामग्री के परिवहन में ट्रक से रेल और फिर रेल से ट्रक जैसे कई चरणों में बदलाव करना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की हानि होती थी. अब खनन क्षेत्रों और विद्युत संयंत्र स्थलों पर प्रत्यक्ष रेलवे साइडिंग्स बनने से यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो गई है.उन्होंने कहा, खनन स्थल और बिजली संयंत्रों पर सिर्फ अंतिम चरण की कनेक्टिविटी सुधारने से ही बिजली उत्पादन की लागत पर बड़ा प्रभाव पड़ता है क्योंकि लॉजिस्टिक खर्च घट जाता है. इससे उद्योगों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होता है.

डिजिटल उपकरणों से और मजबूत होगा मिशन- कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मिशन को- और सशक्त बनाने के लिए नए डिजिटल टूल्स लॉन्च किए. इसमें एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफेस शामिल है, जो आम नागरिकों को गति शक्ति डेटाबेस तक सार्वजनिक पहुंच की सुविधा देगा. साथ ही, एक बहु-क्षेत्रीय रिपोर्टिंग प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे मिशन के क्षेत्रवार विकास पर प्रभाव की निगरानी की जा सकेगी.

भविष्य में कर्मचारियों के लिए पंजीकरण अभियान

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर. सरकार ने कर्मचारी भविष्य योजना में छूटे हुए पात्र श्रमिकों के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है जो पहली नवंबर से अगले साल 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि यह अभियान सामाजिक सुरक्षा के तहत ऐसे कर्मचारियों के नामांकन को बढ़ावा देगा और नियोक्ताओं को पिछले रिकॉर्ड को नियमित करने में मदद करेगा जिनका नाम किसी वजह से ईपीएफ में शामिल होने से रह गया है. ईपीएफओ में पंजीकृत नियोक्ता उन सभी मौजूदा कर्मचारियों का नामांकन कर सकते हैं, जो पहली जुलाई, 2017 से 31 अक्टूबर, 2025 के बीच प्रतिष्ठान की नौकरी में जुड़े हैं किंतु किसी भी कारण से पहले ईपीएफ योजना में नामांकित नहीं हुए हैं.

आगे बढ़ेगा भारत और कनाडा संबंध

आर्थिक, रणनीतिक और लोगों के बीच संबंधों पर रहेगा फोकस- जयशंकर

दोनों देशों के बीच साझेदारी को पुनर्जीवित करने पर हुई चर्चा

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को पदभार संभालने के बाद अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आईं कनाडा की नई विदेश मंत्री अनीता आनंद का स्वागत किया.

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत, कनाडा के साथ सकारात्मक मानसिकता के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने को उत्सुक है, जैसा कि इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी के साथ अपनी मुलाकात में संकेत दिया था.

राष्ट्रीय राजधानी में हुई द्विपक्षीय बातचीत के दौरान जयशंकर ने टिप्पणी की कि पिछले कुछ महीनों में भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंध लगातार प्रगति कर रहे हैं. उन्होंने कहा, हम अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक तंत्रों को बहाल करने और पुनर्जीवित करने पर काम कर रहे हैं. जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कानानास्किस में प्रधानमंत्री कार्नी के साथ अपनी बैठक के दौरान कहा था, भारत का दृष्टिकोण सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ना है.

सहयोग की दृष्टि पर हुई चर्चा

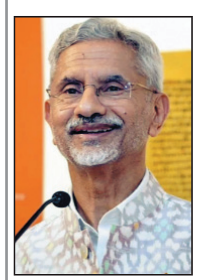

जयशंकर ने बताया कि विदेश मंत्री आनंद ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की, जहां प्रधानमंत्री ने सहयोग की दृष्टि और इसे साकार करने के सर्वोत्तम तरीके की रूपरेखा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत की. उन्होंने दोनों देशों के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों, विदेश और व्यापार मंत्रालयों के बीच हुई व्यापक चर्चाओं पर प्रकाश डाला. जयशंकर ने कनाडा की ओर देखते हुए कहा, हम एक पूरक अर्थव्यवस्था, एक और खुला समाज, विविधता और बहुलवाद देखते हैं. हमारा मानना है कि यही एक घनिष्ठ, टिकाऊ और दीर्घकालिक सहकारी ढांचे का आधार है.

फॉक्सकॉन करेगी तमिलनाडु में 15 हजार करोड़ का निवेश

मुख्यमंत्री स्टालिन से मुलाकात के बाद फॉक्सकॉन की घोषणा

निवेश से इंजीनियरिंग और कुशल युवाओं को मिलेगा रोजगार

चेन्नई, 13 अक्टूबर. वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु में अपने उन्नत प्रौद्योगिकी निर्माण कार्यों के विस्तार के लिए 15 हजार करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है.

इस निवेश से राज्य में 14 हजार उच्च मूल्य वाले रोजगार सृजित होंगे, जिनमें अधिकतर अवसर इंजीनियरिंग स्नातकों और कुशल युवाओं के लिए होंगे.

राज्य सरकार की निवेश संवर्द्धन एजेंसी गाइडेंस तमिलनाडु ने जानकारी दी कि यह निर्णय फॉक्सकॉन और तमिलनाडु सरकार के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी को और मजबूत करेगा.

मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन से मुलाकात के बाद निर्णय- यह घोषणा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और फॉक्सकॉन के भारत प्रतिनिधि रॉबर्ट वू के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल की बैठक के बाद की गई. इस दौरान राज्य के उद्योग मंत्री टी. आर. बी. राजा भी उपस्थित रहे.

तकनीक आधारित उत्पादन की ओर बढ़ेगी कंपनी

फॉक्सकॉन का यह निवेश भारत में उसकी विकास यात्रा के अगले चरण का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत कंपनी पारंपरिक असेंबली कार्यों से आगे बढ़कर तकनीक-आधारित उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देगी.उद्योग मंत्री ने कहा कि भारत में स्थापित होने वाला पहला ‘फॉक्सकॉन डेस्क’ सभी परियोजनाओं के सुचारू और मिशन मोड में क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगा.

ट्रस्टी बनें निवेशकों की पहली ढाल

ट्रस्टीज को विकसित करनी होगी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली

एएमसी की आंतरिक नियंत्रण जांच हो स्वतंत्र और निष्पक्ष: सेबी

मुंबई, 13 अक्टूबर. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडेय ने सोमवार को म्यूचुअल फंड ट्रस्टीज से आग्रह किया कि वे उद्योग और निवेशकों की सुरक्षा के लिए प्रभावी गार्डरेल्स तैयार करें तथा ऐसी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करें, जिससे किसी भी अनियमितता का समय रहते पता लगाया जा सके और आवश्यक कदम उठाए जा सकें.

सेबी द्वारा आयोजित लीडरशिप डायलॉग फॉर ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड कार्यक्रम को

संबोधित करते हुए पांडेय ने कहा कि ट्रस्टीज म्यूचुअल फंड प्रणाली में पारदर्शिता और जोखिम प्रबंधन के लिए पहली सुरक्षा पंक्ति हैं.उन्होंने कहा, जब आवश्यकता हो, तो ट्रस्टीज को सवाल उठाने, मामले को आगे बढ़ाने और जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करने का अधिकार है. यह अधिकार अपने साथ निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नैतिक जिम्मेदारी भी लाता है और इसके लिए निर्भीक होकर कदम उठाने की जरूरत है.

नियंत्रण प्रणाली की स्वतंत्र जांच जरूरी

सेबी प्रमुख ने ट्रस्टीज से आग्रह किया कि वे एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्वतंत्र जांच करें, अनुपालन रिपोर्ट पर सवाल उठाएं और आवश्यकता पड़ने पर धारणाओं को चुनौती दें. उन्होंने कहा कि ट्रस्टीज को डेरिवेटिव्स, वैकल्पिक परिसंपत्तियों, ईएसजी निवेश और जोखिम विश्लेषण जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में विशेषज्ञ प्रशिक्षण लेना चाहिए ताकि वे प्रभावी निगरानी कर सकें .निगरानी केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि गहराई तक होनी चाहिए.

खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 99 महीने के निचले स्तर पर

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर. सब्जियों और दालों की कीमतों में भारी गिरावट के कारण सितंबर में उपभोक्ता मूल्य पर आधारित मुद्रास्फीति (खुदरा महंगाई दर) 99 महीने के निचले स्तर पर आ गयी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, सालाना आधार पर सितंबर में खुदरा महंगाई की दर 1.54 प्रतिशत रही जो जून 2017 के बाद का निचला स्तर है.

इससे पहले, अगस्त 2025 में खुदरा महंगाई दर 2.04 प्रतिशत दर्ज की गयी थी. इस दौरान खाद्य मुद्रास्फीति शून्य से 2.28 प्रतिशत नीचे रही जो दिसंबर 2018 के बाद सबसे कम है. अगस्त में यह शून्य से 0.64 प्रतिशत नीचे रही थी.

सोने की कीमतों में बंपर उछाल

24 कैरेट सोना 12,573 प्रति ग्राम तक पहुंचा

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर 2025. धनतेरस से पहले भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं. त्योहारों के इस शुभ मौके पर देशभर में सोना खरीदने की होड़ मच गई है, जिससे बाजार में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने की कीमतों में तेज़ी बनी हुई है. चेन्नई में 24 कैरेट सोना 12,573 प्रति ग्राम तक पहुंच गया है, जबकि दिल्ली में इसकी कीमत 12,555 प्रति ग्राम दर्ज की गई है.

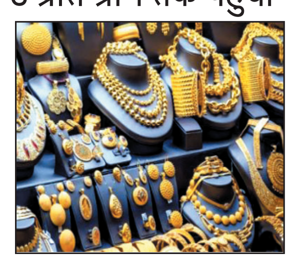

मुंबई, पुणे, भोपाल और अहमदाबाद जैसे प्रमुख शहरों में भी गोल्ड रेट 12,540-12,545 प्रति ग्राम के बीच है. वहीं, 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के भाव में भी लगातार तेजी बनी हुई है. बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक अनिश्चितता, डॉलर में उतार-चढ़ाव और घरेलू मांग की वजह से कीमतें चढ़ रही हैं. ऐसे में अगर आप सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन निवेश के लिए बेहद खास हो सकता है.

धनतेरस और दिवाली से पहले भारत में सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं. त्योहारों की खरीदारी, शादी-ब्याह का मौसम और निवेश की भावना—तीनों मिलकर सोने के बाजार को गर्म कर रहे हैं.

सब्जियां और दालें हुई सस्ती

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर. सितंबर 2025 में आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है. खुदरा महंगाई दर गिरकर सिर्फ 1.54 प्रतिशत पर आ गई, जो कि जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है. इससे पहले अगस्त में यह 2.07 प्रतिशत थी. खाने-पीने की चीज़ों जैसे सब्ज़ियों, दालों, फलों और खाद्य तेलों के दामों में गिरावट से ये राहत देखने को मिली है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, फूड इनफ्लेशन सितंबर में -2.28 प्रतिशत रहा, जो दिसंबर 2018 के बाद का सबसे कम स्तर है. आरबीआई ने भी महंगाई के अनुमान को कम करते हुए अब 2025-26 के लिए इसे 2.6 प्रतिशत पर रखा है. इससे आर्थिक स्थिरता और आम आदमी की जेब दोनों को राहत मिलने की उम्मीद है. सितंबर 2025 में भारत में खुदरा महंगाई दर गिरकर 1.54 प्रतिशत पर आ गई, जो कि पिछले 8 वर्षों का सबसे निचला स्तर है. अगस्त 2025 में यह दर 2.07 प्रतिशत थी. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, इस गिरावट का मुख्य कारण खाद्य वस्तुओं की कीमतों में भारी गिरावट है.

शेयर बाजार में आई भारी गिरावट

मुंबई, 13 अक्टूबर. पहले कारोबारी दिन सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ, जब निवेशकों ने वैश्विक संकेतों और अमेरिका-चीन तनाव के चलते मुनाफावसूली को तरजीह दी.

सेंसेक्स 173.77 अंक या 0.21 प्रतिशत गिरकर 82,327.05 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58 अंक या 0.23 प्रतिशत टूटकर 25,227.35 अंक पर आ गया. दिनभर के कारोबार में सेंसेक्स 82,043.14 अंक तक और निफ्टी 25,152.30 अंक तक नीचे फिसल गया था.

स्पाइसजेट को क्रिसिल से ए4 प्लस रेटिंग

एयरलाइन के पुनर्गठन प्रयासों और पूंजी जुटाने की सराहना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर. विमानन कंपनी स्पाइसजेट को प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने ‘ए4 प्लस’ रेटिंग दी है. यह रेटिंग कंपनी के चल रहे पुनर्गठन, वित्तीय अनुशासन और पूंजी जुटाने की क्षमता को देखते हुए दी गई है. क्रिसिल ने अपने नोट में कहा है कि एयरलाइन की स्थिर तरलता स्थिति और ऋण पुनर्गठन में प्रगति उसके भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत हैं.

कंपनी ने हाल ही में क्यूआईपी के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है. इसके अलावा, स्पाइसजेट ने 2026 तक 10 पुराने विमानों को हटाने और 18 नए विमानों को डैम्प लीज पर जोड़ने की योजना बनाई है. यह कदम एयरलाइन की परिचालन क्षमता को लगभग 2.5 गुना बढ़ा देगा.

त्योहारी सीजन में बढ़ती यात्रा मांग और अतिरिक्त उड़ानों की तैनाती से स्पाइसजेट के लाभ में सुधार की उम्मीद की जा रही है. कंपनी के पास फिलहाल 333 करोड़ रुपये की मुक्त नकदी और 150 करोड़ रुपये की प्रतिबंधित नकदी मौजूद है. इससे उसके परिचालन और लीज भुगतान को लेकर कोई चिंता नहीं है.

सीएम तेजस्वी, 3 डिप्टी सीएम!

महागठबंधन का ‘सीट-बंटवारा’ फॉर्मूला तैयार

पटना. बिहार विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है और विपक्षी महागठबंधन ने सत्ता में वापसी के लिए एक बड़ा सियासी दांव चला है. गठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव का चेहरा लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा तीन उपमुख्यमंत्री बनाने के फॉर्मूले को लेकर है.

यह रणनीति न केवल सहयोगियों को साधने की कोशिश है, बल्कि इसके जरिए तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की परंपरागत छवि को बदलकर एक नया सामाजिक समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं. महागठबंधन के इस नए फॉर्मूले के तहत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सबसे बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और लगभग 125 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं, कांग्रेस के हिस्से में 50 से 55 सीटें और वाम दलों को करीब 25 सीटें मिलने की संभावना है. राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी के अनुसार, बची हुई सीटें विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) और अन्य सहयोगियों को दी जाएंगी.

सामाजिक समीकरण साधने की बड़ी कोशिश

तीन उपमुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव महागठबंधन की सबसे बड़ी रणनीति है. इसके तहत अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो एक-एक उपमुख्यमंत्री दलित, मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग से बनाया जाएगा. कांग्रेस नेता प्रवीन सिंह कुशवाहा इसे राहुल गांधी के सामाजिक समावेशन के संदेश का प्रतिबिंब बताते हैं, तो वहीं वीआईपी प्रवक्ता देव ज्योति ने दावा किया है कि एक उपमुख्यमंत्री का पद उनकी पार्टी के नेता मुकेश साहनी को मिलेगा.

मणिपुर में क्यों नहीं बन रही है सरकार?

इंफाल. मणिपुर में क्या होगा किसी को समझ में नहीं आ रहा है. राष्ट्रपति शासन लगे हुए छह महीने से ज्यादा हो गए हैं. मोटे तौर पर शांति बहाल हो गई है. प्रधानमंत्री की यात्रा भी हुई, जिसके बाद छिटपुट हिंसा को छोड़ कर कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है. फिर भी सरकार नहीं बन पा रही है.

कहा जा रहा था कि जल्दी ही सरकार बन जाएगी और उसके बाद मणिपुर के राज्यपाल, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला वापस लौटेंगे और दिल्ली के उप राज्यपाल बनेंगे. लेकिन मणिपुर में सरकार नहीं बनी. कहा जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को किनारे करने की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है. मैती समुदाय के विधायक उनके साथ हैं.

पिछले दिनों मणिपुर विधानसभा के स्पीकर टी सत्यब्रत सिंह दिल्ली आए. भाजपा के कुछ और विधायक भी उसी समय दिल्ली पहुंचे थे. सब चाहते हैं कि सरकार बने. क्योंकि अगले चुनाव में अब डेढ़ साल का समय बचा है. अगर लोकप्रिय सरकार बनानी है तो उसे काम करने के लिए कुछ समय भी देना होगा.

मायावती की मुश्किल है डगर पनघट की...

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के राजनीति में मायावती एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाने में जुटी हुई हैं. बसपा सुप्रीमो अपनी राजनीति को धार देकर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में बहुजन समाज पार्टी के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करती दिख रही है. दरअसल, एक दशक से भी अधिक समय से बहुजन समाज पार्टी को प्रदेश की राजनीति में खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

यूपी चुनाव 2012 में मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी सरकार का पतन हुआ. उसके बाद से बसपा यूपी की सत्ता में फिर से स्थापित नहीं हो पाई है. लोकसभा चुनाव 2014 में प्रदेश की राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द-गिर्द सिमटी दिखाई दी. मोदी लहर का असर यूपी चुनाव 2017 में बड़े पैमाने पर दिखाई दिया. लोकसभा चुनाव 2014 में बसपा का खाता नहीं खुला.

मायावती ने प्रदेश में बढ़ रही राजनीतिक चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव 2019 में बड़ा निर्णय लिया. अपने प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया. उस समय बुआ यानी मायावती और बबुआ यानी अखिलेश यादव की जोड़ी को यूपी की राजनीति में अहम करार दिया गया. हालांकि, इस जातीय समीकरण के गठजोर को जमीन पर उतरने में दोनों ही दल सक्षम नहीं हुए. नतीजा लोकसभा चुनाव 2019 में दिखा. लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा एक बार फिर 62 सीटों पर जीती. एनडीए को 64 सीटों पर जीत मिली. बसपा-सपा गठबंधन 15 सीटें ही जीत पाई. इसमें बसपा के खाते में 10 सीटें गईं. सपा 2014 की तरह ही पांच सीटों पर जीत दर्ज कर पाई. इस प्रकार मायावती का प्रयोग असफल रहा.

मायावती ने बदली रणनीति

प्रदेश में लगातार खराब प्रदर्शन के बाद अब मायावती ने रणनीति में बदलाव किया है. यूपी चुनाव 2027 से करीब 16-17 माह पहले से तैयारी को शुरू किया गया है. कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर लखनऊ कार्यक्रम से पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि बसपा एक बार फिर खड़ी हो रही है. हालांकि, उनके सामने तीन चुनौतियां बड़ी हैं. बसपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी की है. ऐसे में मायावती क्या सपा के पीडीए तिलिस्म को तोड़ पाने में कामयाब होती हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा.

पहली बार हो रहा उपचुनाव, भाजपा- कांग्रेस में है ये है कॉमन फैक्टर

इस सीट ने तीन बार दिए मंत्री

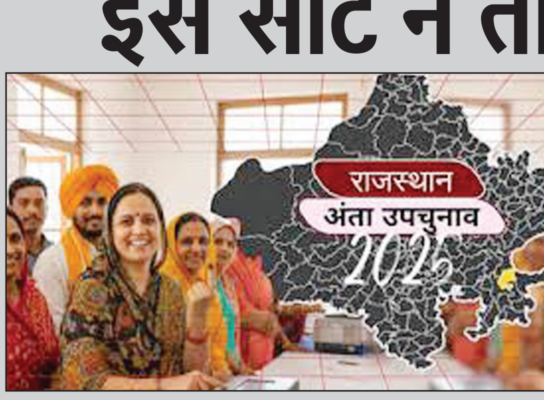

बारां. बारां जिले की अंता विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा होते ही इलाके में चुनाव को लेकर सर गर्मियां तेज हो गई. 11 नवंबर को वोटिंग होगी. अंता सीट के मतदाता नए विधायक के चुनाव के लिए वोट करेंगे. यह विधानसभा सीट साल 2008 में बनी थी.

अब तक चार विधानसभा चुनाव इस सीट पर हो चुके हैं. और सीट ने तीन बार मंत्री दिए. इस सीट पर बीजेपी-कांग्रेस मुकाबले में दो-दो बार जीत कर बराबरी पर है. पहली बार इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है. ऐसे में मतदाताओं में भी चुनाव को लेकर उत्साह बना है. पहली बार इस विधानसभा सीट पर साल 2008 में कांग्रेस के नेता प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज की थी. वह मंत्री बने थे. उसके बाद बीजेपी ने पैराशूट के तौर बाहरी नेता प्रभुलाल सैनी को यहां से साल 2013 में चुनाव लड़वाया और वह जीते और वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री बने थे.

कंवरलाल को मिली सजा तो खाली हुई ये सीट- साल 2018 में विधानसभा चुनाव हुआ और प्रभुलाल सैनी को प्रमोद जैन भाया ने शिकस्त दी. भाया चुनाव जीते और फिर मंत्री बने. लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया चुनाव हार गए. बीजेपी ने इस बार प्रभुलाल सैनी की जगह पैराशूट के तौर पर झालावाड़ जिले से कंवरलाल मीणा को अंता विधानसभा सीट पर उतारा. बीजेपी इस फार्मूले में कामयाब हुई. साल 2023 में प्रमोद जैन भाया पर खुद कांग्रेस नेता भरत सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे. बीजेपी ने उन आरोपों को चुनाव में भुनाया. प्रमोद जैन भाया अंता विधानसभा सीट पर चुनाव हार गए. लेकिन कंवरलाल मीणा जीतने के बाद उनकी विधायकी लंबी नहीं चल पाई. अपनी विधायकी 20 साल पुराने मामले में कोर्ट से सजा मिलने पर गंवानी पड़ी. 1 मई को कंवरलाल मीणा की विधायकी खत्म हो गई.

अंता विधानसभा सीट का अब तक का इतिहास यह रहा है कि लगातार यहां पर एक पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई है.

कंवरलाल की पत्नी पर भी दांव खेल सकती है बीजेपी

भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पूरी तरह से जीतना चाहती है. पार्टी यहां पूरी मशीनरी संगठन की लगा देगी. ऐसे में विधायक पद से निलंबित हुए कंवरलाल मीणा की पत्नी भगवती को भी भाजपा अंता सीट पर उपचुनाव प्रत्याशी बना सकती है. उनके समर्थक पार्टी कार्यकर्ता यह कयास लगा रही हैं. पार्टी कंवरलाल मीणा के जेल जाने की सिंपैथी ले सकती है. इधर आज संयोग ऐसा रहा कि पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी उपचुनाव की घोषणा वाले दिन बारां प्रवास पर रहे. लेकिन उनके लिए कहा जा रहा है कि वह अंता से चुनाव नहीं लड़ेंगे. लेकिन पार्टी उनके नाम पर भी दांव लगा सकती है. क्योंकि एक बार वह यहां से विधायक रह चुक हैं और मंत्री भी रहे हैं.